सरकारी नौकरी के लिए विधवाओं और तलाक शुदा महिलाओं के लिए आयु सीमा

2091. **कुमारी सईदा खातून** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तलाकशुदा महिलाओं और विधवाओं हेतु सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिये आयु सीमा 30 वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस आयु सीमा को बढ़ाने का विचार रखती है;

(ग) सरकार उनके परिवारों के पालन पोषण हेतु उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है; और

(घ) सरकार 30 वर्ष से अधिक आयु वाली ऐसी महिलाओं के लिए जो योजनाएं कार्यान्वित कर रही है उनका ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्यक्रम और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) वेतन आयोग ने आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश की है ।

(ग) और (घ) तलाकशुदा महिलाओं और विधवाओं के परिवारों के पालन-पोषण के लिए सरकार की कोई विशेष योजना नहीं है । फिर भी वे महिलाएं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों, संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वासन हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों/संस्थाओं की स्थापना, रोजगार/शिशु गृहों के लिए महिलाओं के प्रशिक्षण की परियोजनाओं जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत सहायता पाने की पात्र हैं ।

Recognition to the Employees Association of Nehru Memorial Museum and Library

2092. SHRI SUKOMAL SEN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Nehru Memorial Museum and Library Employees' Association has applied to the authorities for its recognition;

(b) if so, whether recognition has since been accorded; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No, Sir, as the rules relating to recognition of employees' associations have not yet been finalised.

जमालपुर रेलवे वर्कशाप

2093. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीजल और विद्युत इंजिनों की मरम्मत और सवारी डिब्बे/माल डिब्बे बनाने का काम जमालपुर स्थित रेलवे वर्कशाप को नहीं दिया गया है; और

(ख) क्या विशेष, प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के शिश प्रशिक्षण के लिए सीटों और जमालपुर वर्कशाप में इनका प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर उनके पदों की संख्या में वृद्धि किए जाने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) रेलों की कुल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारतीय रेलों के विभिन्न कारखानो को कार्य आबंटित किया जाता है । किसी कारखाना विशेष को उसकी अवस्थिति तथा उपलब्ध अवसंरचना सुविधाओ के आधार पर उपयुक्ततम कार्य आबंटित

किया जाता है। जमालपुर कारखाना को डीजल रेल इंजनों की आवधिक ओवरहाल का अतिरिक्त कार्य आवंटित किया गया है। इसे 140 टन की डीजल क्रेनों के निर्माण का कार्य भी आवंटित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत ग्रामीण बच्चों को सुविधायें उपलब्ध कराया जाना

2094. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई शिक्षा नीति से उन ग्रामीण बच्चों को, जो अभी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं या स्कूल पहुंच कर भी बीच में ही छोड़ देते हैं, क्या लाभ होने की संभावना है;

(ख) क्या इस नीति से अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूलों को तेजी से बढ़ती हुई संख्या रूकेगी और एक सूत्रीय भाषा के अन्तर्गत राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राष्ट्रवाद और अखण्डता की भावना पैदा होगी; और

(ग) क्या प्रत्येक गांव के बच्चों को खेल के मैदान, खेल का सामान, पुस्तकालय और शिक्षा के अन्य साधन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार उन सभी बच्चों को जो 1990 तक लगभग 11 वर्ष की आयु के हो जाएंगे उन्हें अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से पांच वर्ष की स्कूली अथवा इसके समकक्ष शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस नीति का यह भी लक्ष्य है कि असमानताओं को दूर किया जाए और उन बच्चों की, जो अब तक समानता से वंचित रहे है, विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर समान शैक्षिक अवसर प्रदान किये जाये। उन बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जो स्कूल जाने में असमर्थ है अथवा जिन्होंने प्रवेश के बीच-बीच में ही स्कूल छोड़ दिया है, अनौपचारिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार की है जिसमें वांछित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख है। "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" नाम एक सांकेतिक कार्यक्रम को शुरू करने की परिकल्पना की गई है ताकि प्राथमिक स्कूलों में (i) दो बड़े कमरे, जो कि हर मौसम में प्रयोग में आ सकें (ii) आवश्यक खिलौने (iii) ब्लैक बोर्ड (iv) नकशे (v) चार्ट (vi) अन्य शिक्षण सामग्रियां (vii) कम से कम दो शिक्षक, जिनमें से एक महिला हो, इसके साथ-साथ शिक्षकों की संख्या यथाशीघ्र बढ़कर प्रति कक्षा एक अध्यापक हो जाए, जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके। आशा की जाती है कि इन सुविधाओं की व्यवस्था होने से सामान्य स्कूलों तथा पब्लिक स्कूलों के अन्तराल को काफी सीमा तक समाप्त किया जा सकेगा।

सरकार की नीति प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृ भाषा में प्रदान करना तथा त्रि भाषा सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर पर बच्चों को दूसरी और तीसरी भाषा पढ़ाने की है।

नीति में खेल कूद तथा शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के एक अभिन्न भाग के रूप में महत्व दिया गया है। कार्रवाई योजना में अधिक मात्रा में और शारीरिक शिक्षा उपस्कर और सुविधाएं मुहैया करने की परिकल्पना है।